(SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU) : (a) and (b) The latest estimated cost of the project is Rs. 105.90 crores. The anticipated expenditure upto March, 1995 is Rs. 33.14 crores. VIII Plan outlay for the project is Rs. 87.00 crores. No. Irrigation Potential has been created out of the ultimate potential of 35,450 hectares.

(c) to (e) The project is likely to spill over beyond VIII Plan. Its completion date depends upon priority attached and the funds allocation by the State Government.

नहरों से जल का रिसाव

7554. **श्री आस मोहम्मद:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टेढ़ी-मेढ़ी नहरों से होने वाले रिसाव के कारण 25 प्रतिशत जल की हानि होती है जो कि बाढ़ आने का मुख्य कारण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने 31 मार्च, 1995 तक नहरों में रिसाव को रोकने के लिए क्या प्रयास किए हैं तथा इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राजय मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू): (क) और (ख) नहरों में रिसाव और वाष्पीकरण के कारण सतही प्रणाली से होने वाली जल हानि 25 से 45 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न है जो मृदा विशेषताओं तथा अन्य तथ्यों पर निर्भर करती है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा भूजल की भरपाई कर देती है। नहरों से रिसाव के कारण हुई बाढ़ की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) नहरों में रिसाव को कम करने के लिए वित्तीय प्रभाव और लागत प्रभावकारिता को ध्यान में रखते हुए, सुभेद्य पहुंचों के चुनिन्दा स्तरों को पक्का किया जाता है।

गुजरात में भू-जल स्तर में कमी होना

7555. **श्री अनन्तराम देवशंकर दवे:**
श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में विशेषकर सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भू-जल स्तर में तेजी से कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने राज्य में भूजल की उपलब्धता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू): (क) और (ख) गुजरात में, विशेषकर सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भूजल स्तर में तेजी से कोई गिरावट नहीं देखी गई है। तथापि, भूजल के स्तर के दीर्घावधिक प्रेक्षणों से पता चला है कि जूनागढ़, अमरेली, जामनगर, राजकोट, सुरेन्द्र नगर, कच्छ, भावनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सावरकांठा, मेहसाणा और बनासकांठा जिलों के विशेष स्थानों में भूजल स्तर में धीरे-धीरे गिरावट हुई है।

(ग) जी, हां।

(घ) गुजरात में केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण और अन्वेषण के अनुसार, राज्य के भूजल संसाधनों की उपलब्धता 22551.71 मिलियन घन मीटर आंकी गई है।

(ङ) भूजल के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं का पूरा किया जाना

7556. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात की उन निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके पूरा होने में तीन वर्ष से अधिक का विलंब हो गया है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं;

(ग) इनके पूरा होने में विलंब के परिणामस्वरूप इनकी लागत में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को वर्तमान समय-सारणी में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडु): (क) और (ग) विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के कारण मोटे तौर पर ये हैं:

(1) तकनीकी: व्यवहार्यता रिपोर्ट बनाने के लिए समिति अन्वेषण और परिणामस्वरूप क्रियान्वयन के दौरान परियोजना के व्याप्ति क्षेत्र और डिजाइन में परिवर्तन, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों आदि के लिए मूल अनुमानों में अपर्याप्त प्रावधान।

(2) वित्तीय: निर्माण के दौरान मूल्यों में वृद्धि, पर्याप्त निधियों का उपलब्ध न होना, भूमि अधिग्रहण की लागत बढ़ जाना।

(3) अन्य कारण: श्रम समस्या, ठेके संबंधी समस्याएं, पर्यावरणविदों एवं भूमिविस्थापितों द्वारा आन्दोलन, प्राकृतिक आपदाएं।

(घ) सरकार द्वारा उठाये गए विभिन्न कदमों में ये शामिल है; उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देना जिन पर काफी प्रगति हो चुकी है, महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए परिव्यय निर्धारित करना, चुनिन्दा परियोजनाओं की सघन मानीटरी, लागत नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए राज्यों को सलाह देना।

विवरण

गुजरात की अनुमोदित वृहद, मध्यम और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं, जो अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं, का ब्यौरा

क्र० सं०	परियोजना का नाम	योजना जिसमें शुरू की गई	अनुमानित लागत	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लागत में वृद्धि
वृहद परियोजनाएं					
1.	दमनगंगा	IV	24.40	214.95	190.55
2.	पानम	IV	10.67	84.33	73.66
3.	साबरमती	IV	17.59	110.72	93.13
4.	कर्जन	V	37.20	264.09	226.89
5.	सिपू	वार्षिक योजना 78-80	18.80	92.75	73.95
6.	सूखी	V	23.11	113.40	90.29
7.	वटराक	वार्षिक योजना 78-80	43.70	63.03	19.33
8.	जंखारी	VI	18.70	78.70	60.00
मध्यम परियोजनाएं					
1.	हिरन-II	IV	3.05	12.20	9.15
2.	सुखभादर	V	2.75	22.05	19.30
3.	मलूंदरी	V	1.73	21.05	19.32
4.	कलूभार	V	3.13	21.62	18.49
5.	मच्छूनाला	V	0.90	16.82	15.92
6.	अमली (वर-II)	V	0.20	24.13	23.85
7.	दिंयू	V	1.04	56.90	55.94
8.	वेनू-II	V	3.25	23.78	20.53

क्र० सं०	परियोजना का नाम	योजना जिसमें शुरू की गई	अनुमानित लागत	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लागत में वृद्धि
9.	उंड (जीवापुर)	V	3.97	38.37	34.50
10	पादर (पीएमएस)	पांचवीं	13.11	47.93	34.82
11	हाटक	पांचवीं	6.70	25.23	18.45
12	केलिया	पांचवीं	2.84	21.01	18.17
13	गुहाई	पांचवीं	9.13	71.53	62.40
14	सरनव-II	पांचवीं	3.49	8.20	4.71
15	मानी	पांचवीं	1.82	12.20	10.38
16	अमिपुर	पांचवीं	2.79	9.62	6.83
17	लमरिया	पांचवीं	2.82	6.73	3.91
18	अजौ-III	वार्षिक योजना 78-80	13.23	28.54	15.31
19	बुहू	वार्षिक योजना 78-80	5.76	41.42	35.66
20	मुक्तेश्वर	छठी	5.37	22.80	17.43
विस्तार / नवीकरण / आधुनिकीकरण					
1	खारीकुट आधुनिकीकरण	छठी	3.10	3.81	0.71
2	पतेहवाड़ी आधुनिकीकरण	छठी	24.76	40.56	15.80
3.	दतियावाड़ा आधुनिकीकरण	छठा	34.88	45.70	10.82
4	शतरुंजी आधुनिकीकरण	छठी	26.68	40.65	13.97
5	भादर आधुनिकीकरण	छठी	18.60	24.05	5.45
6	उकई वकरापर आधुनिकीकरण	छठी	60.12	60.12	—

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के मेधावी छात्रों के लिए विद्यालय

7557. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध विशिष्ट विद्यार्थियों में प्रतिभा को विकसित करने के लिए कितने विशिष्ट विद्यालय खोले गए हैं;

(ख) इन विशिष्ट विद्यालयों के भवन परिसर निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप किन-किन स्थानों पर निर्मित नहीं किए जा सके हैं तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) इनमें से किन विशिष्ट विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु निर्धारित आवश्यक राशि में सरकारी भूमि दस वर्षों से अधिक समय से उपलब्ध होने के बावजूद विद्यालय भवन परिसरों का निर्माण नहीं हो पाया है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार इन विशिष्ट विद्यालयों के निर्माण हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता देती रही है और यदि हां, तो इन भवनों के निर्माण हेतु दी गई सहायता तथा इस संबंध में लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) अनुसूचित जनजातियों के विशेष मेधावी छात्रों में मेधा विकास के लिए मध्य प्रदेश में 15 विशेष विद्यालय खोले गए हैं। इन विद्यालयों की अवस्थिति से सम्बन्धित ब्यौरा संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) 15 विद्यालयों में से 7 विद्यालयों के भवन परिसरों का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप किया गया है। अन्य शेष विद्यालयों